शोध साहित्य SHODH SAHITYA
INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL
(समसामयिक विषयों पर केंद्रित बहुविषयक मासिक ई-शोध पत्रिका)
E-ISSN 2584-2447
Impact Factor – SJIF 2024 = 3.621
Vol -3
Issue -2
February
2025

रेडियो की आत्मनिर्भरता का आलोचनात्मक मूल्यांकन

(आकाशवाणी के लिए गठित विभिन्न समितियों के विशेष सन्दर्भ में)

योशिता पांडेय
शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड

प्रस्तावना

जनसंचार के सशक्त माध्यम के रूप में आज भी रेडियो को ही माना जाता है। रेडियो प्रसारण जब कुशलता से उपयोग किया जाता है, तो संचार का सबसे प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। रेडियो एक आत्मनिर्भर माध्यम नहीं है, लेकिन जब इसे समूह, स्वागत और समूह चर्चा के साथ जोड़ा जाता है, जब इसे लिखित शब्द के माध्यम से संचार के दो-तरफा चैनल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और जब इसे ग्रामीण विकास के लिए समग्र योजना में व्यवस्थित रूप से बनाया जाता है, तो यह आधुनिक युग के लिए आवश्यक परिवर्तनों में एक प्रमुख कारक हो सकता है। रेडियो का उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचने और विकासशील देशों में मौजूद कई स्थानीय - अक्सर अलिखित-भाषाओं में संचार के लिए सरल और सस्ते तरीके से किया जा सकता है। वस्तुतः सभी राष्ट्रों के पास अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं, सांस्कृतिक डिजाइनों और बुनियादी नैतिकताओं के अनुरूप रेडियो कार्यक्रम बनाने की एक निश्चित क्षमता है।

भारत में 80% से अधिक लोग लगभग 55,000 गाँवों में रहते हैं। कई गाँव शारीरिक और मानसिक रूप से अलग-थलग हैं। भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सड़कों से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। 75% से अधिक वयस्क आबादी निरक्षर है। आज ऑल इंडिया रेडियो सभी भाषाओं और लगभग 50 बोलियों में लगभग 30 घंटे प्रतिदिन ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित करता है। दुनिया के सभी हिस्सों में, रेडियो जनसंचार माध्यमों में सबसे सर्वव्यापी है। विकासशील देशों में, रेडियो एकमात्र ऐसा साधन है जिसे वास्तव में जनसंचार कहा जा सकता है, जहाँ रेडियो प्रसारणों द्वारा बड़ी संख्या में निवासियों तक पहुँचा जा सकता है और उन्हें प्राप्त करने के तरीके भी हैं। किसी अन्य माध्यम में सूचना, शैक्षिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए इतने सारे लोगों तक पहुँचने की क्षमता नहीं है।

आज, स्वामित्व और कार्यक्रम प्रवाह के संदर्भ में रेडियो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय संचार माध्यम हो सकता है। इन लाभों के बावजूद, रेडियो भाषा और तकनीकी बाधाओं के कारण संचार के एक अंतरराष्ट्रीय माध्यम के रूप में सीमित है, संगीत के क्षेत्र में जहाँ यह एक सार्वभौमिक भाषा को बढ़ावा देता है। मैक ब्राइड रिपोर्ट के अनुसार 1973 के आसपास, 187 देशों और क्षेत्रों के एक विश्व सर्वेक्षण में उनमें से केवल तीन का पता चला जहाँ कोई प्रसारण सुविधाएँ नहीं हैं भूटान, लिकटेंस्टीन और सैन मैरिनो। ऑल इंडिया रेडियो ने भूटान में रेडियो स्टेशन बनाकर उसे तीन के समूह से बाहर निकलने में मदद की। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान दुनिया में अनुमानित एक अरब रिसीवर थे, यानी पृथ्वी पर हर चार व्यक्तियों में से लगभग एक। लेकिन आज, देशों के बीच और भीतर सूचना और संचार में अंतर समानता के विकास के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आइए हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रति 1000 निवासियों पर रेडियो की संख्या पर एक नजर डालें। 1997 में, एशिया में 900विकसित देशों में 1061 और सबसे कम विकसित देशों में प्रति 1000 निवासियों पर 142 रेडियो सेट थे। दक्षिण अफ्रीका को किसी तरह से तीसरी दुनिया में प्रथम विश्व देश कहा जा सकता है। इसमें प्रति 1000 निवासियों पर दस गुना से भी अधिक रेडियो सेट हैं। अंतर-देशीय अंतर, निश्चित रूप से, बहुत बड़ा हो सकता है (स्केयर एंड रेनिंग, 2002)।

भारत में प्रसारण के 80 वर्ष

मार्कोनी ने 2 जून 1896 को रेडियो का आविष्कार किया था, यानी ठीक 120 साल पहले और ऑल इंडिया रेडियो 8 जून 1936 को अस्तित्व में आया। नियमित प्रसारण की स्थापना तब हुई जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के पहले महानिदेशक जॉन रीथ ने भारत में प्रसारण शुरू करने के लिए लियोनेल फील्डन को पहला प्रसारण नियंत्रक नियुक्त किया।

भारत में ग्रामीण प्रसारण की उत्पत्ति

ग्रामीण प्रसारण शुरू करने का पहला निश्चित प्रयास बॉम्बे स्टेशन द्वारा किया गया था जिसने 1933 में मराठी, गुजराती और कन्नड़ में नियमित कार्यक्रम शुरू किए, पहला सामुदायिक सेट थाना भिवंडी में स्थापित किया गया था। भारत में ग्रामीण प्रसारण के

शुरुआती प्रयास 1935 में कुछ प्रांतीय सरकारों (उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (अब पाकिस्तान)) द्वारा दी गई सब्सिडी के रूप में हुए थे। 1930 के दशक की शुरुआत में, इंग्लैंड की मारकोनी कंपनी ने पेशावर में स्थापित किए जाने वाले एक रेडियो ट्रांसमीटर और कुछ गांव सेट उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत की सरकार को उपहार में दिए और बाद में इसका इस्तेमाल ग्रामीण श्रोताओं के लिए एक कार्यक्रम पेश करने के लिए किया (फील्डन, 1939)। ट्रांसमीटर द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र के लगभग 100 गांवों को इन प्रसारणों का लाभ उठाने के लिए बैटरी से चलने वाले रेडियो सेट प्रदान किए गए और अगले वर्ष पंजाब सरकार ने ग्रामीण प्रसारण के कुछ उपयोगी अनुभव प्राप्त किए और प्रयोग किसी भी तरह से मूल्यहीन नहीं था। कुछ नाटक प्रसारित किए गए, और ये न केवल लोकप्रिय साबित हुए, बल्कि उन पाठों में भी बेहद प्रभावी साबित हुए, 1939। पेशावर और मद्रास ट्रांसमीटरों को अंततः आकाशवाणी ने अपने अधीन ले लिया, जिसने तुरंत ही उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को पुनर्गठित करने के कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। पंजाब के 1935 के प्रयोग में यह दिखाने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं था कि क्या कठिनाइयाँ आने की संभावना है या ग्रामीण रेडियो पर कितनी दूर तक प्रतिक्रिया देंगे। प्रयोग के परिणामस्वरूप, ग्रामीणों का केवल एक छोटा सा दैनिक दर्शक वर्ग ही आकर्षित हुआ, इसे कम से कम कहें तो, हर दिन हर हजार में पचास और यह कि ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करने और साथ ही साथ वांछित जानकारी और निर्देश देने के लिए पर्याप्त विविधता देने के लिए बहुत ही सरलता और बहुत अधिक काम करना आवश्यक है। प्रयोग ने आगे पाया कि यह एक भ्रांति थी। ग्रामीण अपने घरों में कभी नहीं सुनते या तो वे लाउडस्पीकर पर आते हैं या वे नहीं सुनते" (फील्डन, 1939)। मिदनापुर योजना के तहत 1935 में मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट श्री पी. जे. ग्रिफिथ द्वारा बंगाल में एक और ग्रामीण प्रसारण प्रयोग किया गया। धन की अनुपलब्धता के कारण योजना लागू नहीं हो सकी। 15 गांवों में सामुदायिक सेट लगाने में दो साल लगे, जबकि राज्य सरकार ने 870 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई (फील्डन, 1939, पृ. 42-46)। लाहौर में रेडियो स्टेशन खुलने और पंजाब सरकार के रिसीविंग सेट को दिल्ली के आसपास से लाहौर में स्थानांतरित करने के कारण, यह माना गया कि इस क्षेत्र में ग्रामीण प्रसारण बंद हो जाएगा। लेकिन दिल्ली मुख्यालय होने के कारण, यह अन्य राज्यों को आगे

बढ़ाने की स्थिति में था। ऑल इंडिया रेडियो के अनुसंधान विभाग ने एक उपयुक्त ग्रामीण रिसीवर विकसित किया, जो पूरे भारत में बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए सुविधाजनक और सस्ता था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कुछ समय से प्रयोग चल रहे थे और काफी काम किया गया था। लेकिन यह महसूस किया गया कि वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि अनुसंधान विभाग कामकाजी परिस्थितियों में काम करने वाले ग्रामीण रिसीवरों के साथ निकट संपर्क में रहे। इसलिए, प्रयोग और अनुसंधान के दृष्टिकोण से यह वांछनीय था कि दिल्ली ग्रामीण प्रसारण में प्रयोगों का केंद्र बनी रहे। ग्रामीण प्रसारण शुरू करने का पहला निश्चित प्रयास बॉम्बे स्टेशन द्वारा किया गया था जिसने 1933 में मराठी, गुजराती और कन्नड़ में नियमित कार्यक्रम शुरू किए, पहला सामुदायिक सेट थाना भिवंडी में स्थापित किया गया था। भारत में ग्रामीण प्रसारण के शुरुआती प्रयास 1935 में कुछ प्रांतीय सरकारों (उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (अब पाकिस्तान)) द्वारा दी गई सब्सिडी के रूप में हुए थे। 1930 के दशक की शुरुआत में, इंग्लैंड की मारकोनी कंपनी ने पेशावर में स्थापित किए जाने वाले एक रेडियो ट्रांसमीटर और कुछ गांव सेट उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत की सरकार को उपहार में दिए और बाद में इसका इस्तेमाल ग्रामीण श्रोताओं के लिए एक कार्यक्रम पेश करने के लिए किया (फील्डन, 1939)। ट्रांसमीटर द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र के लगभग 100 गांवों को इन प्रसारणों का लाभ उठाने के लिए बैटरी से चलने वाले रेडियो सेट प्रदान किए गए और अगले वर्ष पंजाब सरकार ने ग्रामीण प्रसारण के कुछ उपयोगी अनुभव प्राप्त किए और प्रयोग किसी भी तरह से मूल्यहीन नहीं था। कुछ नाटक प्रसारित किए गए, और ये न केवल लोकप्रिय साबित हुए, बल्कि उन पाठों में भी बेहद प्रभावी साबित हुए, 1939। पेशावर और मद्रास ट्रांसमीटरों को अंततः आकाशवाणी ने अपने अधीन ले लिया, जिसने तुरंत ही उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को पुनर्गठित करने के कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। पंजाब के 1935 के प्रयोग में यह दिखाने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं था कि क्या कठिनाइयाँ आने की संभावना है या ग्रामीण रेडियो पर कितनी दूर तक प्रतिक्रिया देंगे। प्रयोग के परिणामस्वरूप, ग्रामीणों का केवल एक छोटा सा दैनिक दर्शक वर्ग ही आकर्षित हुआ, इसे कम से कम कहें तो, हर दिन हर हजार में पचास और यह कि ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करने और साथ ही साथ वांछित जानकारी और निर्देश देने के लिए पर्याप्त विविधता

देने के लिए बहुत ही सरलता और बहुत अधिक काम करना आवश्यक है। प्रयोग ने आगे पाया कि यह एक भ्रांति थी। ग्रामीण अपने घरों में कभी नहीं सुनते या तो वे लाउडस्पीकर पर आते हैं या वे नहीं सुनते" (फील्डन, 1939)। मिदनापुर योजना के तहत 1935 में मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट श्री पी. जे. ग्रिफिथ द्वारा बंगाल में एक और ग्रामीण प्रसारण प्रयोग किया गया। धन की अनुपलब्धता के कारण योजना लागू नहीं हो सकी। 15 गांवों में सामुदायिक सेट लगाने में दो साल लगे, जबकि राज्य सरकार ने 870 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई (फील्डन, 1939, पृ. 42-46)। लाहौर में रेडियो स्टेशन खुलने और पंजाब सरकार के रिसीविंग सेट को दिल्ली के आसपास से लाहौर में स्थानांतरित करने के कारण, यह माना गया कि इस क्षेत्र में ग्रामीण प्रसारण बंद हो जाएगा। लेकिन दिल्ली मुख्यालय होने के कारण, यह अन्य राज्यों को आगे बढ़ाने की स्थिति में था। ऑल इंडिया रेडियो के अनुसंधान विभाग ने एक उपयुक्त ग्रामीण रिसीवर विकसित किया, जो पूरे भारत में बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए सुविधाजनक और सस्ता था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कुछ समय से प्रयोग चल रहे थे और काफी काम किया गया था। लेकिन यह महसूस किया गया कि वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि अनुसंधान विभाग कामकाजी परिस्थितियों में काम करने वाले ग्रामीण रिसीवरों के साथ निकट संपर्क में रहे। इसलिए, प्रयोग और अनुसंधान के दृष्टिकोण से यह वांछनीय था कि दिल्ली ग्रामीण प्रसारण में प्रयोगों का केंद्र बनी रहे।

नई योजना जिसका उद्घाटन 16 अक्टूबर 1938 को दिल्ली के मुख्य आयुक्त माननीय श्री ई.एम. जेनकिंस ने किया था, का उद्देश्य पूरे दिल्ली प्रांत को रिसीविंग सेटों के नेटवर्क से कवर करना है। इस योजना में कुल मिलाकर 120 रिसीविंग सेट लगाने का प्रावधान है, जिन्हें दिल्ली प्रांत के 381 गांवों में से सबसे अधिक आबादी वाले गांवों में लगाने का प्रस्ताव है, ताकि 600 या उससे अधिक आबादी वाले लगभग हर गांव को इसकी जरूरत पूरी हो सके। इन रिसीवरों के तकनीकी रखरखाव के उद्देश्य से, दिल्ली प्रांत को पांच सर्किलों या क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात नजफगढ़, नांगलोई, नरेला, महरौली और दिल्ली, जिनमें से प्रत्येक में एक चार्जिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव है। इससे 6 से 8 मील की दूरी के भीतर

का हर गांव चार्जिंग यूनिट से जुड़ जाएगा और बारिश के दौरान भी जब सड़क की स्थिति अनुकूल नहीं होती है, तब भी सेटों का नियमित रखरखाव संभव हो जाएगा। (फील्डन, 1939पृष्ठ 49)। अप्रैल 1937 में, बॉम्बे सरकार ने 18 ग्रामीण सेट खरीदे और उनमें से 16 स्थापित किए। बॉम्बे सरकार ने ग्रामीण कार्यक्रमों के एक निदेशक और दो मैकेनिकों से युक्त एक तकनीकी स्टाफ नियुक्त किया। बाद वाले को थाने के कलेक्टर की सीधी निगरानी में रखा गया और बॉम्बे स्टेशन को रविवार को छोड़कर हर दिन मराठी में एक घंटे का कार्यक्रम देने के लिए कहा गया। कार्यक्रम का संचालन पूरी तरह से बॉम्बे सरकार द्वारा नियुक्त ग्रामीण कार्यक्रम निदेशक के हाथों में था, हालांकि कार्यक्रम का वित्तपोषण ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया जाता था। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हुई। कार्यक्रम अनाकर्षक थे और सेट शायद ही कभी चालू हालत में पाए जाते थे।

युद्ध के अंत में और विभाजन के बाद, ऑल इंडिया रेडियो का सामान्य विस्तार हुआ, जिसमें गांवों के लिए सुनने की सुविधा और कार्यक्रम उपलब्ध कराना सबसे महत्वपूर्ण उपाय था। क्षेत्रीय कस्बों में नए स्टेशन स्थापित किए गए, नए मीडियम और शॉर्ट-वेव ट्रांसमीटर लगाए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य सुनने की कवरेज बढ़ाना था। स्वतंत्रता के बाद, जब पंचवर्षीय योजनाएँ लागू की गईं, तो पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं ने आकाशवाणी को गांवों में रहने वाले लाखों लोगों तक व्यावहारिक सहायता पहुँचाने के साधन में बदल दिया। इस उद्देश्य से पहले, दर्शक शहरी केंद्रित थे। ग्रामीण दर्शकों की संख्या कुल प्रसारण का केवल एक छोटा हिस्सा थी। हालाँकि, ग्रामीण कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी 28 स्टेशनों (जो मौजूद थे) से 48 बोलियों में, लगभग 25 घंटे प्रतिदिन प्रसारित किए जाते थे। आदिवासी क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी हैं। (माथुर और पॉल, 1959)। भारत में रेडियो सेट का परिदृश्य स्वतंत्रता से पहले, भारत में रेडियो सेट का निर्माण नहीं किया जाता था। उन्हें आयात किया जाता था। आयातित रेडियो सेट की कीमत 400 रुपये या उससे अधिक थी, जो कि सबसे अमीर भारतीय परिवारों और निवासी यूरोपीय लोगों को छोड़कर सभी की पहुंच से बाहर थी। बड़े शहरों में बसे दर्शकों - अंग्रेजी बोलने वाले, बिजली से संपन्न और उच्च पश्चिमी संस्कृति के लिए साझा स्वाद - ने एक स्पष्ट रूप से परिभाषित बाजार प्रस्तुत किया (जिविन, 1998)।

लागतों को पूरा करने के लिए, सरकार ने रेडियो उपकरणों पर पचास प्रतिशत आयात शुल्क लगाया, जिससे प्रसारण अधिकांश भारतीय दर्शकों की पहुंच से और भी दूर हो गया (फील्डन, 1939, पृष्ठ 2-5)।

1954 में भारत सरकार एक नई योजना लेकर आई जिसके तहत प्रत्येक समुदाय की लागत का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष राज्य सरकार और ग्रामीणों द्वारा वहन किया जाएगा। सेट में एक लाउडस्पीकर, एक एरियल किट और एक बैटरी पैक शामिल होना था, जब तक कि गांव में बिजली न हो और कीमतें 300 रुपये से 250 रुपये के बीच होती थीं (माथुर और पॉल, 1959)। सामुदायिक सेटों का रखरखाव कुछ राज्यों में ग्रामीणों द्वारा और अन्य में राज्य द्वारा भुगतान किए गए मैकेनिकों द्वारा किया जाता है, लागत गांव समुदाय द्वारा वहन की जाती है। रखरखाव की प्रणाली में काफी बदलाव किया जा रहा है और अब इस उद्देश्य के लिए हर राज्य में एक मानक संगठन स्थापित किया जा सकता है। (माथुर और पॉल, 1959पृ. 17)। पूना प्रयोग पर चर्चा करने से पहले कनाडाई फार्म रेडियो फोरम के बारे में कुछ जानकारी होना उचित है। यूनेस्को ने 1952-53 में कनाडाई राष्ट्रीय फार्म रेडियो फोरम प्रयोग के परिणाम प्रकाशित किए हैं। लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले ही कनाडा में सीखे गए सबक फ्रांस में ग्रामीण दर्शकों के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों के विकास में लागू किए जा रहे थे। फ्रांस के काम के परिणामस्वरूप इटली और जापान में और प्रयोग किए गए।

इसके समानांतर, दक्षिण-पूर्व एशिया के किसी देश में, ग्रामीण दर्शकों के लिए 'चर्चा प्रकार के रेडियो कार्यक्रम के उपयोग पर एक पायलट परियोजना आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जो यथासंभव कनाडा के फार्म रेडियो फोरम के अनुभव पर आधारित थी। भारत सरकार की पेशकश और जो प्रयोग किया गया, वह कोई और नहीं बल्कि पूना में 'फार्म रेडियो फोरम में एक भारतीय प्रयोग' था।यूनेस्को ने मई 1955 में यूनेस्को के महाधिवेशन के आठवें सत्र में स्वीकृत परियोजना के आधार पर एक प्रस्ताव दिया और अक्टूबर 1955 में सूचना एवं प्रसारण सचिव पी.एम .लाड ने कुछ चर्चाएँ कीं और तत्पश्चात परियोजना शुरू करने के लिए यूनेस्को और भारत सरकार के बीच एक औपचारिक

समझौता हुआ। इस समय तक भारत में प्रसारण 20 वर्ष पुराना हो चुका था और पूरे भारत में उपलब्ध रेडियो सेटों की संख्या 7000 थी। इस दौरान, आकाशवाणी की श्रवण सीमा के भीतर 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों की संख्या 29,000 हो गई थी।

ग्रामीण श्रवण क्लब और कृषि मंच जैसे नवाचार भारत में मौजूद नहीं थे, लेकिन यूनेस्को परियोजना के तहत परियोजना शुरू होने से तीन या चार साल पहले भारत में लगभग 200 कृषि मंच थे (माथुर और पॉल, 1959)। यह प्रयोग कनाडाई मॉडल पर आधारित था और इसे गांव के दर्शकों और रेडियो स्टेशन के प्रोग्रामर के बीच दो-तरफा संचार स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था (चटर्जी, 1991)। कृषि मंच शुरू में कृषि मंच या गांव श्रवण क्लबों का आयोजन बेहतर श्रवण सुनिश्चित करने और कार्यक्रम सामग्री एकत्र करने के सीमित उद्देश्य से किया गया था। कुछ स्टेशनों पर आकाशवाणी ने इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। ये क्लब कुछ हद तक औपचारिक रूप से काम कर रहे थे, जब 1955-56 में कनाडाई पैटर्न पर कृषि मंचों की एक पायलट परियोजना शुरू करने का अवसर आया। इसमें विशेष रूप से नियोजित प्रसारण, श्रवण-और-चर्चा समूहों का गठन और श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन शामिल था।

परियोजना के उद्देश्य

(क) ग्रामीण जीवन और कार्य के विभिन्न पहलुओं पर ग्रामीणों तक जानकारी पहुँचाना जो उनके लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी होगी

(ख) राष्ट्रीय आदर्शों और उपक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में उनके ज्ञान को व्यापक बनानाय

(ग) दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना।

भारत में ग्रामीण प्रसारण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार बताई जा सकती हैं

(क) कार्यक्रम व्यक्तिगत श्रोता के बजाय समुदाय की ओर निर्देशित होते हैं। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण समुदाय के सेट और संगठित सुनने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि गांवों में बहुत कम व्यक्तिगत रेडियो मालिक हैं।

(ख) ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए केवल क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हालांकि कुछ प्रसारणों के लिए सामग्री केंद्रीय मुख्यालय से वितरित की जा सकती है, लेकिन कार्यक्रम वास्तव में क्षेत्रीय होते हैं।

(ग) प्रसारण कार्यक्रम केवल कृषि विषयों पर ही केंद्रित नहीं होते हैं, बल्कि औसत ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को छूते हैं। संगीत, नाटक और फीचर कार्यक्रमों को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है।

कार्यक्रम पैटर्न

ग्रामीण कार्यक्रम की मूल सामग्री थी

क) समाचार, बाजार दरें, मौसम की रिपोर्ट

ख) ग्रामीण श्रोताओं की रुचि के लिए जानकारीपूर्ण बातचीत और चर्चा

ग) नाटक, स्किट और फीचर

घ) संगीत ज्यादातर लोक संगीत

महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रुचि वाले कार्यक्रम। कार्यक्रम की अवधि आमतौर पर आधे घंटे से एक घंटे तक होती थी। विशेष कार्यक्रम जैसे कि कृषि पंडितों (कृषि के लिए राज्य पुरस्कार के विजेता) के साक्षात्कार, आंतरिक गांवों के कार्यों की रिकॉर्डिंग, आदर्श गांवों के दौरे का बाहरी प्रसारण, कभी-कभार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, आम तौर पर सफल रहे हैं। पारंपरिक प्रकार के लोक-संगीत और ग्रामीण नाटक बहुत लोकप्रिय हैं। कार्यक्रम प्रस्तुति की तकनीक जो कई वर्षों में विकसित हुई है, वह चार या पांच बुजुर्गों के एक चौपाल (गांव का क्लब) से है, नेता मानक क्षेत्रीय भाषा में बोलता है - कभी-कभी प्रत्येक एक अलग बोली में। इन पात्रों की अनौपचारिक बातचीत में ज्ञान और सलाह के बिखरे हुए शब्द हैं और स्वस्थ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी के एक घंटे में वे वक्ताओं, नाटकों, गायकों, नकलची आदि का परिचय कराते हैं। कई ऐसा ही एक उदाहरण है लोहा सिंह, जो इसी नाम के एक रेडियो नाटक का केंद्रीय पात्र है, जिसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो, पटना से हुआ था। (कुजूर और झा, 2009)। सबसे पहले, यह तय किया गया कि प्रयोग को एक ऐसे सघन क्षेत्र तक

सीमित रखा जाना चाहिए, जहाँ एक क्षेत्रीय भाषा बोली जाती हो। इस उद्देश्य के लिए बॉम्बे राज्य के पाँच जिलों - पूना, अहमदनगर, नासिक, उत्तरी सतारा और कोल्हापुर का एक मराठी भाषी क्षेत्र चुना गया। दूसरे, यह तय किया गया कि परियोजना का मूल्यांकन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाना चाहिए, और मूल्यांकन का कार्य करने के प्रश्न पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, बॉम्बे से संपर्क किया गया।पूना प्रयोग का 10 साल बाद दूसरा मूल्यांकन किया गया। यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विल्बर श्राम द्वारा किया गया, जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो से संयुक्त निदेशक, फार्म और होम विशेषज्ञ पी.वी. कृष्णमूर्ति और पूना मंचों के पूर्व मुख्य आयोजक और कार्यक्रम विशेषज्ञ डी.डी. जाधव द्वारा सहायता प्रदान की गई।रिपोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणी यह थी कि प्रयोग एक बड़ी सफलता थी। इसमें आगे कहा गया कि हालांकि, रेडियो ग्रामीण मंच के साथ इतने सारे आयोजन और संचालन का अनुभव दुनिया में बेजोड़ है। यह प्रयोग अन्य देशों की योजना में शामिल हो गया, जो अपनी ग्रामीण आबादी के साथ संचार की इस पद्धति को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे (श्राम और कृष्णमूर्ति, 1966)।जनवरी 1959 में मंच योजना को राष्ट्रव्यापी रूप से विस्तारित करने का प्रयास करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कम से कम एक मंच का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बाद में लक्ष्य को घटाकर हर तीन ब्लॉक में एक मंच कर दिया गया। 17 नवंबर 1959 को रेडियो ग्रामीण मंच एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया और इसके तुरंत बाद इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना से जोड़ दिया गया, जिसका लक्ष्य 31 मार्च 1966 को योजना के अंत तक 25,000 मंचों तक पहुंचना था। जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह लक्ष्य संभव नहीं साबित हुआ और इसे घटाकर 15000 कर दिया गया (श्राम और कृष्णमूर्ति, 1966)। ओडिशा में भी मंचों को समर्थन देने का एक लंबा इतिहास रहा है और केरल ने भी विशेष प्रयास किए हैं।

हाथरोन प्रभाव - एक नई चीज को आजमाने की प्रेरणा, और अंतरराष्ट्रीय ध्यान का केंद्र होना - ने पूना में प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद की होगी, लेकिन 1960 में यह प्रभावकारी नहीं रहा। भारत में कोई भी राज्य अपने मंचों के लिए इतना क्षेत्रीय समर्थन नहीं जुटा पाया है जितना पूना परियोजना ने

जुटाया था, जैसे कि प्रत्येक जिले में एक पूर्णकालिक आयोजक, पांच जिलों से संबंधित एक मुख्य आयोजक के अलावा, और कुछ अंशकालिक आयोजक। कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर पाया है।

(1) 1961 में दिल्ली में राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र द्वारा,

(2) 1962 में लखनऊ में योजना अनुसंधान कार्य संस्थान द्वारा,

(3) 1962 में हैदराबाद के पास उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह द्वारा।

श्रम और कृष्णमूर्ति ने देखा कि "क्षेत्र से प्राप्त हमारी कुल धारणा यह रही है कि देहाती रेडियो गोष्ठी (रेडियो ग्रामीण मंच) कार्यक्रम को, जैसा कि यह क्षेत्र में है, अभी भी एक संगठनात्मक संरचना विकसित करनी है जिसमें कई भौतिक कारकों को सफलतापूर्वक हल किया जाना चाहिए"। दिल्ली रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि 'रेडियो ग्रामीण मंचों ने दिल्ली के गांवों की सामाजिक संरचना में एक स्थान पा लिया है'। उस्मानिया रिपोर्ट में कहा गया, 'यह एक उत्कृष्ट माध्यम है, इसे ग्रामीणों को शिक्षित करने के माध्यम के रूप में पर्याप्त रूप से मान्यता दी जानी चाहिए'।

श्रम की रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि सबसे सामान्य आवश्यकताएं हैं, एक सघन समुदाय, जिसमें लगभग एक ही तरह की कृषि समस्याएं होंय एक समुदाय जिसमें यथासंभव कम आंतरिक संघर्ष होय और एक समुदाय जो किसी बड़े शहर की छाया से बाहर हो। महानगर के आठ से दस मील के भीतर के गाँव ग्रामीण की बजाय उपनगरीय होते हैं, और जाहिर है, ग्रामीण मंच उनके लिए क्या कर सकता है, इसमें उनकी कम रुचि होती है।

विद्यालंकार समिति

सरकार द्वारा नियुक्त विद्यालंकार समिति ने अपनी रिपोर्ट (1963) में ग्रामीण कार्यक्रमों और गाँवों में इन्हें सुनने की सुविधाओं के बारे में कुछ कठोर बातें कही थीं। रिपोर्ट में कहा गया था कि सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा आपूर्ति किए गए कुछ रिसीविंग सेटों का रखरखाव खर्च इतना अधिक था कि समुदायों के लिए इनका रखरखाव करना अब संभव नहीं था। यह अनुमान लगाया गया है कि किसी भी समय 'बीमार सेटों' की संख्या लगभग 35% थी। समिति ने ग्रामीण कार्यक्रमों की अवधि को शाम को लगभग ढाई घंटे और सुबह और

दोपहर में एक-एक घंटे तक बढ़ाने की मांग का भी जोरदार समर्थन किया और सिफारिश की कि यह लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में हासिल किया जाना चाहिए (लूथरा, 1986)। 1965 में, ऑल इंडिया रेडियो के तत्कालीन महानिदेशक पी.पी. भट्ट और पी.वी. कृष्णमूर्ति ने 1965 में यूनेस्को में एक और शोधपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पूना परियोजना में प्रयुक्त संचार लाइनों की व्याख्या की गई। 1966 पूना प्रयोग के बाद - 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किसानों तक नई कृषि तकनीक पहुंचाने में रेडियो के योगदान को समझते हुए, तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम ने देश के सात ऑल इंडिया रेडियो स्टेशनों पर फार्म और होम यूनिट शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारत में कृषि प्रसारण के एक नए युग की शुरुआत की। यदि ऑल इंडिया रेडियो सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में अपनी भूमिका का श्रेय ले सकता है, तो वह ग्रामीण और कृषि प्रसारण के क्षेत्र में भी ऐसा कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं, खासकर, हरित क्रांति रेडियो के उपयोग के बिना इतनी जल्दी नहीं आ सकती थी। रेडियो की शैक्षिक और विकासात्मक भूमिका ग्रामीण श्रोताओं के लिए इसके कार्यक्रमों से कहीं अधिक स्पष्ट है।

सामग्री निर्माण का प्रबंधन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह रुचि उत्पन्न करने तथा कृषक समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है, एक दो-स्तरीय प्रबंधन समूह की स्थापना की गई है। प्रथम स्तर का समूह राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर नीतिगत मुद्दों को तैयार करेगा तथा उनसे निपटेगा। दूसरा समूह प्रसारक के स्तर पर गठित किया जाएगा, जो सामग्री निर्माण की वास्तविक मांग तथा उसके प्रसारण में संलग्न होगा। ऑल इंडिया रेडियो (किसान वाणी स्टेशन) कृषि विभाग द्वारा विभिन्न विषयों जैसे बीज उपचार, बीज क्रय करते समय सावधानियां, अंतर-फसल, कीटनाशक क्रय करते समय सावधानियां, एकीकृत कीट प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन तथा धान एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर निर्मित त्वरित समाचार प्रसारित करता है, जिसके माध्यम से फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार के लिए किसानों की तकनीकी जागरूकता के लिए निःशुल्क वाणिज्यिक समय का समुचित उपयोग किया जाता है।

आदर्श वाक्य

भारत के राष्ट्रीय प्रमुख सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रूप में, आकाशवाणी अपनी स्थापना के बाद से ही जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने के आदर्श वाक्य के साथ काम कर रहा है, जो वास्तव में अपने आदर्श वाक्य - बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खरा उतर रहा है।

शैक्षिक प्रसारण

रेडियो का उपयोग दुनिया भर में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रारूपों में व्यापक भौगोलिक विस्तार में स्थित अत्यधिक विविध दर्शकों के लिए किया जाता रहा है - सभी कम प्रतिशत उत्पादन लागत पर। साक्षरता बाधा को पाटने की इसकी क्षमता काफी पहले ही देखी जा चुकी थी। जबकि सभी आकाशवाणी कार्यक्रमों का जोर - चाहे आम श्रोता के लिए हो, या किसानों, महिलाओं, बच्चों, छात्रों, शिक्षकों या औद्योगिक श्रमिकों जैसे विशिष्ट समूहों के लिए, व्यापक अर्थों में शिक्षा पर है, कुछ कार्यक्रमों की योजना एक विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य के साथ बनाई गई है।

ऑल इंडिया रेडियो के शैक्षणिक कार्यक्रम

फोन-इन-प्रोग्राम रेडियो के माध्यम से प्रसारित होने वाले फोन-इन-प्रोग्राम के विभिन्न प्रकार हैं। इन कार्यक्रमों में श्रोता विशेषज्ञों से जुड़ते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं और विशेषज्ञ श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यह रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित होने वाला बहुत ही रोचक और संवादात्मक कार्यक्रम है।

रेडियो वार्ताः प्रत्येक रेडियो स्टेशन रेडियो वार्ता प्रसारित करता है। ये वार्ताएँ विभिन्न विषयों पर आधारित होती हैं। विषय त्योहार, शिक्षा, सूचना, जागरूकता और भाईचारे आदि से संबंधित होते हैं।

खुला आकाशः यह कार्यक्रम विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए विज्ञान और शोध विषय पर आधारित कार्यक्रम है। हर दिन विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम की अवधि 25 मिनट है।

ऑल इंडिया रेडियो द्वारा भारत में शैक्षणिक परियोजनाएँ

स्कूल प्रसारण परियोजनारू स्कूल प्रसारण परियोजना पहली शैक्षिक रेडियो परियोजना थी। इसे 1937 में शुरू किया गया था और दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे से शुरू किया गया था। यह स्कूली छात्रों के लिए कार्यक्रम था।

वयस्क शिक्षा और सामुदायिक विकास परियोजना) रेडियो फोरम - (यह रेडियो परियोजना 1956 में शुरू की गई थी। यूनेस्को की मदद से, इस परियोजना को सबसे पहले पुणे के 144 गाँवों के ग्रामीणों पर आजमाया गया था। यह कृषि आधारित परियोजना थी, और इसे श्रेडियो फोरम परियोजना नाम दिया गया था। यह कार्यक्रम आकाशवाणी का पहला सफल शैक्षणिक कार्यक्रम था।

खेत और घर प्रसारण परियोजनाः यह परियोजना 1966 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य किसान और ग्रामीण थे। इसका उद्देश्य किसानों को शिक्षित करना और स्थानीय प्रासंगिकता के अनुसार अपने खेतों में नवीन पद्धतियों को अपनाने में उनकी सहायता करना था।

विश्वविद्यालय प्रसारण परियोजनाः यह परियोजना 1965 में उच्च शिक्षा के छात्रों को लक्षित करने के लिए शुरू की गई थी। कार्यक्रम दो प्रकार के थे -सामान्य और संवर्धन। सामान्य कार्यक्रमों में सार्वजनिक हित के विषय शामिल थे और संवर्धन कार्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में दी जाने वाली पत्राचार शिक्षा का समर्थन करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार अध्ययन विद्यालय और हैदराबाद का केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान आकाशवाणी के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की तैयारी और प्रसारण के लिए प्रसिद्ध हैं।

भाषा शिक्षण कार्यक्रमः 1979 में, आकाशवाणी और राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने जयपुर और अजमेर जिलों के 500 प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को हिंदी सिखाने के लिए हाथ मिलाया। इस परियोजना को श्रेडियो पायलट परियोजना कहा गया, क्योंकि यह प्रायोगिक आधार पर थी। यह परियोजना सफल रही और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में दोहराई गई।

इग्नू-आकाशवाणी प्रसारणः जनवरी 1992 में प्रमुख इग्नू कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी ने इग्नू के साथ सहयोग किया। प्रारंभ में, मुंबई, हैदराबाद और शिलांग के आकाशवाणी केंद्रों ने यह सेवा शुरू की। यह कार्यक्रम अभी भी मुंबई और हैदराबाद में प्रसारित किया जा रहा है। 9.7 इग्नू-एआईआर इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग (आईआरसी) इग्नू ने आकाशवाणी, भोपाल के सहयोग से 1998 में इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग (आईआरसी) शुरू की। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मुक्तध्पारंपरिक विश्वविद्यालयों के छात्रों के

लिए था। इसकी बड़ी सफलता के तुरंत बाद, आकाशवाणी ने अन्य शहरों में विस्तार किया- लखनऊ, पटना, जयपुर, शिमला, रोहतक, जालंधर, दिल्ली और जम्मू। अब तक, आकाशवाणी के 186 रेडियो स्टेशनों से हर रविवार को एक घंटे (शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक) के लिए इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग (आईआरसी) प्रदान की जा रही है।

ज्ञान-वाणी (भारत का शैक्षिक एफएम रेडियो चैनल)

2001 में मुक्त पारंपरिक विश्वविद्यालयों के छात्रों को लक्षित करने के लिए शुरू किया गया, यह भारत का एकमात्र समर्पित शैक्षिक रेडियो चैनल है। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान और वाणी का अर्थ है हवाई प्रसारण। ज्ञानवाणी स्टेशन मीडिया सहकारी समितियों के रूप में काम करते हैं, जिसमें विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे इग्नू, एनसीईआरटी, यूजीसी, आईआईटी, डीईसी आदि द्वारा योगदान किए गए दैनिक कार्यक्रम शामिल हैं। प्रत्येक स्टेशन की सीमा लगभग 60-किलोमीटर की होगी, जो पूरे शहर-कस्बे के साथ-साथ आसपास के परिवेश को व्यापक पहुँच के साथ कवर करेगी। ज्ञानवाणी पंचायती राज पदाधिकारियों, महिला सशक्तिकरण, उपभोक्ता अधिकार, मानवाधिकार, बाल अधिकार, स्वास्थ्य शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, सतत शिक्षा, विस्तार शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, दलितों के लिए शिक्षा, आदिवासियों के लिए शिक्षा और बहुत कुछ सहित जागरूकता कार्यक्रमों से भी निपटता है।

रेडियो पाठ

रेडियो का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से पाठ्य डेटा हस्तांतरण के साथ-साथ रेडियो-पाठ वातावरण बनाने के लिए किया गया है। शिक्षण अंत आम तौर पर एक एफएम रेडियो स्टेशन होता है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से डेटा प्रसारण की सुविधा होती है। रेडियो प्रसारण के मुख्य बिंदुओं को पाठ्य मोड के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त करने वाले छोर पर भेजा जाता है। सीखने वाले छोर पर रेडियो सुनने की सुविधा के साथ-साथ पाठ्य डेटा प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन भी है। चूंकि ऑडियो और टेक्स्ट दोनों एक साथ प्रसारित होते हैं, इसलिए प्राप्त करने वाले छोर पर सीखने वाले को उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाली शिक्षा मिलती है। यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक, भारत में रेडियो-पाठ के उपयोग पर एक प्रयोग के

परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत से अधिक शिक्षार्थी संतुष्ट हुए। इसका उपयोग प्रसारण के बाद प्राप्तकर्ता छोर पर सहकर्मी समूह चर्चा के लिए भी किया जाता है, जो दर्शाता है कि रेडियो-पाठ का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

अध्ययन में ऑल इंडिया रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। यह भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, खासकर दूरदराज और हाशिए के समुदायों में। जबकि चुनौतियाँ मौजूद हैं, प्रभावशाली शैक्षिक प्रोग्रामिंग की क्षमता महत्वपूर्ण बनी हुई है। इन चुनौतियों का समाधान करके और रणनीतिक सिफारिशों को लागू करके पूरे देश में शैक्षिक समानता को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। ऑल इंडिया रेडियो ने 1936 में अपनी स्थापना के बाद से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने व्यापक नेटवर्क और पहुंच के साथ, शैक्षिक सामग्री को व्यापक दर्शकों तक फैलाने में सहायक रहा है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सीमित है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दिया है।

साहित्य की समीक्षा

1. हेरोल्ड बो मैककेरी (1939) ने कॉलेज रेडियो स्टेशन की भूमिका की जांच की और पाया कि अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 25 रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए थे, जिनमें से 60% शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे, जो स्कूल से पहले या बाद में किए गए थे और इसके साथ ही पाठ्यक्रम पर परामर्श किया गया था और यहां पाया गया कि लगभग सभी शिक्षक उस समय व्यस्त रहते थे और वे विशेषज्ञ नहीं थे और अधिकांश रेडियो स्टेशन नहीं चल सकते थे क्योंकि विश्वविद्यालय उन्हें चलाने में सक्षम नहीं थे और लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे।
2. लिलियन ई. (1950) ने शिक्षा और संचारक के जन माध्यमरू रेडियो की जांच की। इसका उद्देश्य यह अध्ययन करना था कि रेडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए कैसे प्रभावी था। विद्वान ने नोट किया कि स्कूली छात्रों द्वारा सुने जाने वाले 16 से 25 घंटे के कार्यक्रम थे।

3. यूनेस्को (1979 कुआलालंपुर बैठक का उद्देश्य शैक्षिक प्रसारण में समस्याओं पर चर्चा करना और अनुभव का आदान-प्रदान करना था। क्षेत्र में प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना और ग्रामीण समुदायों की शिक्षा और विशेष आवश्यकताओं के विकास के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।
4. इग्नू (2001) ने भारत के शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क के रूप में ज्ञान वाणी की भूमिका की जांच की और बताया कि ज्ञान वाणी देश में एक प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम बन गया है। अध्ययन से पता चला कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र लक्षित समूह थे और ज्ञान वाणी ने आधुनिक समय में शिक्षा सेवाओं की पूर्ति की है। अध्ययन ने सुझाव दिया कि ज्ञान वाणी को सीखने की प्रक्रिया में अधिक संख्या में छात्रों को शामिल करने के लिए नियमित कक्षा से पहले और वैकल्पिक कक्षा में प्रसारित किया जाना चाहिए।
5. शर्मा (2002) ने ज्ञान वाणी के विशेष संदर्भ में भारत के शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क की जांच की और बताया कि ज्ञान वाणी भारत में एक प्रमुख शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम के रूप में उभरा है। अध्ययन से पता चला कि ज्ञान वाणी कार्यक्रम देश में व्यापक शोध और परामर्श दृष्टिकोण पर आधारित था। विद्वान ने सुझाव दिया कि भारत में एफएम रेडियो शैक्षिक प्रसारण की स्थिति को बढ़ाने के लिए ज्ञान वाणी को सामग्री, समय, अवधि और गुणवत्ता के संदर्भ में उचित परिवर्तनों और संशोधनों के माध्यम से समृद्ध किया जाना चाहिए।

ऑल इंडिया रेडियो

रेडियो एक व्यापक माध्यम बन गया है। यह एक अत्यंत आकर्षक माध्यम है जिसे अधिकांश राष्ट्रों ने अपने विकास और सामाजिक परिवर्तन प्रयासों के लिए अपनाया है। निश्चित रूप से कई देशों ने इन लाभों को पहचाना है। ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) प्रसारण की भाषाओं की संख्या के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। स्वतंत्रता के समय छह रेडियो स्टेशन और 18 ट्रांसमीटर (6 मीडियम-वेव और 12 शॉर्ट-वेव) थे, जो 11% आबादी और देश के 2.5% को कवर करते थे। आज, आकाशवाणी 420 प्रसारण केंद्रों (01 फरवरी

2017 तक) के विशाल नेटवर्क के साथ कार्यक्रम शुरू करता है, जो देश भर में स्थित 23 भाषाओं और 146 बोलियों में अपनी घरेलू सेवा के साथ सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता के स्पेक्ट्रम की सेवा करता है, जो देश के लगभग 92% क्षेत्र और कुल आबादी के 99.19% तक पहुँचता है।

संदर्भ सूची

1. Baruah, U.L. (1983). This is All India Radio. NewDelhi: Government of India, Ministry of I&B, Publications Division.
2. Bhatt, B.P., & Krishna moorthy, P.V. (1965). Radio broad casting serves rural development. UNESCO.
3. Chatter ji, P.C. (1991). Broad casting in India. New Delhi: Sage Publications India Pvt. ltd.
4. Fielden, L. (1939). Report on the Progress of Broad casting in India. Simla: Government of India.
5. Kujur, G., & Jha,M.N.(2009). Media Support to Agriculture Extension: Success stories of All India Radio. New Delhi: Directorate General All India Radio.
6. Luthra, H.R. (1986). Indian Broad casting. New Delhi: Government of India, Ministry of I&B, Publications Division.
7. Mathur, J.C., & Paul, N. (1959). An Indian Experiment in Farm Radio Forums. Paris, France: UENSCO.
8. Mullick, K.S. (1974). Tangled Tapes. NewDelhi, India: Sterling Publishers Pvt.LTd.
9. Schramm, W., & Krishna moorthy, P.V. (1966). Ten years of the Radio Rural Forum In India. UNESCO.
10. Skare, K., & Renning, H. (2002).Media in Development An evluation of UneSCO's International Programme for the Development of Communication (IPDC). Royal Norwegian Ministry of foreign Affairs.
11. Zivin, J. (1998). The Imagained Regin of the Iron Lecturer: Village Broad casting in Colonial India. Modern Asian Studies, 32(3), 717-738.